भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2890
जिसका उत्तर मंगलवार 13 मार्च, 2018 को दिया जाना है

इलेक्ट्रिक वाहनों हेतु लिथियम-आयन बैटरी

2890. डॉ कंभमपति हरिबाबू:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति ने इलेक्ट्रिक वाहनों हेतु इसरो की लिथियम-आयन बैटरी प्रौद्योगिकी के वाणिज्यिक प्रयोग की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो उक्त समिति के निष्कर्षों की मुख्य विशेषताएं क्या हैं और इससे इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र को संभावित लाभ क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों में बैटरी की लागत कम करने और इनकी प्रयोग अवधि बढ़ाने हेतु क्या उपाए किए गए/किए जा रहे हैं?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) और (ख): जी हां। सचिवों की समिति (सीओएस) की दिनांक 08 जनवरी, 2018 को आयोजित बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ सिफारिश की गई किः-

"अंतरिक्ष आयोग और सक्षम प्राधिकरण से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद इसरो 'मेक इन इंडिया' शर्त के साथ वाणिज्यीकरण हेतु बिना भेद-भाव के इच्छुक पक्षों को अपनी लिथियम आयन बैटरी प्रौद्योगिकी को हस्तांतरित करने पर विचार कर सकता है।"

(ग): सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मेन्यूफेक्चरर्स (एसआईएएम) ने सूचित किया है कि लिथियम आयन सेलों का आयात करके देश में पहले से ही बैटरी पैक की असेंबली/विनिर्माण हो रहा है। इसके अलावा, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) की संशोधित विशेष प्रोत्साहन पैकेज स्कीम (एमएसआईपीएस) नामक एक योजना है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ लिथियम जैसी उन्नत स्टोरेज बैटरियों को शामिल करते हुए इलेक्ट्रॉनिक/टेलिकॉम उत्पादों के विनिर्माण हेतु सहायता शामिल है। इससे बैटरियों के स्थानीय उत्पादन की बढ़ोतरी में मदद मिलेगी और जिसके परिणामस्वरूप बैटरी की लागत में कमी आएगी।

*****